RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 17 FEBRUARY TO 23 FEBRUARY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 26 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

Bitcoin की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड Page 2

जीएसटी चोरी में समन या नोटिस पर सील होंगे बैंक खाते Page 3

बिल्कुल नए अंदाज़ में हुआ जावा 2.1 का लॉन्च Page 7

editoria!

बढ़ती महंगाई

महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत स्पष्ट दिखने लगे हैं. लेकिन, आमदनी और बचत के लिए आमजन का संघर्ष अभी भी जारी है. बीते दिनों घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जारी उछाल चिंता को बढ़ानेवाला है. देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर शतक के करीब पहुंच रही है. पिछले एक वर्ष में पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर लगभग 18 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. ईंधन की ऊंची कीमतों का असर महंगाई पर पड़ेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा. मोदी सरकार के लिए यह संतोषजनक है कि महंगाई अभी भी निर्धारित लक्ष्य सीमा के अंदर ही है. हालांकि, करों में कटौती कर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी लाने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है. ईंधन की कीमतों में जारी बढ़त का असर थोक और खुदरा बाजार पर होगा, जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की महंगाई का सामना करना पड़ सकता है. वर्तमान महीने में घरेलू गैस की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी हो चुकी है. हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी या कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर एक्सचेंज के रेट पर भी निर्भर करती है. महामारी के बाद से उपभोक्ता मांग पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है, फिर भी कोर इन्फ्लेशन (इसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं) बढ़ रही है. हालांकि, पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक हेडलाइन इन्फ्लेशन में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही. गैर-खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव आगे की चुनौतियों को और बड़ा कर सकता है. कीमतों में बढ़त, महामारी की वजह से कारोबार पर पड़े दुष्प्रभाव को मामूली तौर पर कमतर कर सकती है. वस्तुओं की तरह सेवाओं की लागत को आयात जैसे विकल्पों के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है. सैद्धांतिक तौर पर मांग में कमी का असर कीमतों में गिरावट के तौर पर दिखता है, लेकिन बाजार की आंतरिक जटिलताओं के कारण यह पूरी तरह से सच नहीं होता. इसी वजह से बड़े और छोटे उद्यमों के बीच अंतर स्पष्ट होता है. कीमतों को नियंत्रित करने की ताकत की वजह से कोर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. आपूर्ति बाधित होने से कीमतों को बढ़ाने का मौका मिल जाता है. महामारी की वजह से आपूर्ति बाधित हुई, जिसका सबसे अधिक नुकसान छोटे उद्यमों को हुआ. छोटे और मझोले कारोबारों के दोबारा पटरी पर लौटने पर ही आपूर्ति के इस मसले का समाधान हो सकता है. कोर इन्फ्लेशन के दबाव का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक को है. ऐसे में केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2022 में हेडलाइन इन्फ्लेशन पांच प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की उम्मीद कर सकता है. यह आंकड़ा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के अंतर्गत ही रहेगा. अर्थव्यवस्था में जारी सुधार और कोर इन्फ्लेशन में बढ़त के रुख के समानांतर पूंजी प्रवाह के मद्देनजर आरबीआइ को नीतिगत फैसलों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. आगामी महीनों में आर्थिक वृद्धि को बनाये रखने के साथ-साथ महंगाई को नियंत्रण में रखने की चुनौती भी आरबीआइ के लिए परीक्षा होगी.

देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार

जानें पड़ोसी देशों में कैसा है तेल का हाल..?

नई दिल्ली। भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव जहां 90 रुपए के करीब है। वहीं, राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का रेट देश में सबसे अधिक 100.13 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल के लिए यहां पर आपको 92.13 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। वहीं, हमारे पड़ोसी देशों में आधे रेट्स में पेट्रोल बिक रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की बात करें तो यहां कीमत करीब 51 रुपए के आसपास है। वहीं, चीन में एक लीटर पेट्रोल का भाव 74.74 रुपए है। आपको बताते हैं भारत के 5 पड़ोंसी देशों में पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है। इसके अलावा दुनिया के किन देशों में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है।

अब तक कितना महंगा हुआ ईंधन?

फरवरी में अब तक पेट्रोल-डीजल के रेट में 11 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 3.24 रुपए और डीजल 3.47 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें 1 जनवरी को पेट्रोल का भाव 83.71 रुपये था, आज 89.54 रुपये प्रति लीटर है।

3 डिजिट पहुंचने पर हो सकती है मुसीबत

पेट्रोल की कीमतें अगर 3 डिजिट में पहुंचती हैं तो यह सभी के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि अभी पेट्रोल पंपों की ज्यादातर डिस्पेंसिंग यूनिटें दो अंकों के बाद दो दशमल अंकों तक के लिए कैलिब्रेट हैं। यानी ये 99.99 रुपये तक का मूल्य दिखा सकती हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर पेट्रोल की कीमत 100.00 रुपये का आंकड़ा छूती है तो डिस्पेंसिंग यूनिटें 0.00 रुपये दिखाना शुरू कर देंगी।

क्यों बढ़ रहे पेट्रोल-डीज़ल के दाम

भारत में पेट्रोल-डीज़ल का खुदरा भाव वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव से लिंक है। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होता है तो भारत में पेट्रोल-डीज़ल सस्ता होगा। अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो पेट्रोल-डीज़ल के लिए ज्यादा खर्च करना होगा, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव चढ़ता है तो ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाता है, लेकिन जब कच्चे तेल का भाव कम होता है, उस वक्त सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर टैक्स का बोझ डाल देती है।

भारत के 5 पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत

पाकिस्तान - 51.14 रुपए
श्रीलंका - 60.26 रुपए
बांग्लादेश - 76.41 रुपए
नेपाल - 68.98 रुपए
भूटान - 49.56 रुपए

दुनिया के इन 5 देशों में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल

वेनेजुएला - 1.45 रुपए
ईरान - 4.50 रुपए
अंगोला - 17.82 रुपए
अल्जीरिया - 25.15 रुपए
कुबेत - 25.26 रुपए

बर्फबारी ने बिगाड़ा 'तेल का खेल'

कुएं बंद होने से चढ़े क्रूड ऑयल के दाम

एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी कच्चे तेल के दामों तेजी बनी हुई है. दरअसल, अमेरिका के कई इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अमेरिका के टेक्सास राज्य में तेल के कुएं और रिफाइनरीज बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों के समूह ने कहा कि उसने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया था। कच्चे तेल के दाम बढ़ाने में यही दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के समूह के इस बयान से मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। तनाव बढ़ने पर सऊदी अरब से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

बर्फबारी ने बिगाड़ा 'तेल का खेल'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सऊदी अरब क्रूड का सबसे बड़ा निर्यातक है। उधर, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू होने से कच्चे तेल की मांग बढ़ने के भी आसार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 11 सेंट यानी 0.2 फीसदी बढ़कर 63.41 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। सोमवार को ब्रेंट के दाम जनवरी 2020 के बाद से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अमेरिकी पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा 62 सेंट या 1 फीसदी बढ़कर 60.09 डॉलर प्रति बैरल हो गया। बता दें, अमेरिका में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने से सोमवार को टेक्सास के तेल के कुओं और रिफाइनरियों को बंद कर दिया गया। प्राकृतिक गैस और कच्चे पाइपलाइन ऑपरेटरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, टेक्सास में प्रति दिन लगभग 46 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है और 31 रिफाइनरी लगी हैं।

Bitcoin की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

पहली बार 50 हजार डॉलर के पार पहुंचे दाम

मुंबई। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने मंगलवार को कीमत के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। दरअसल बिटकॉइन मंगलवार को पहली बार 50,000 डॉलर (लगभग 36 लाख रुपये) के आंकड़े को पार कर गया। वहीं कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के अलावा कई और कंपनियों के बिटक्वाइन को डिजिटल करेंसी के तौर पर मंजूरी मिल जाने के कारण कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है।

बिटकॉइन ने 50,603 (लगभग 37 लाख रुपये) डॉलर का रिकॉर्ड कायम किया है। यह 0.83 प्रतिशत बढ़कर 48,351 (लगभग 35.2 लाख रुपये) था।इस साल अब तक बिटकॉइन की कीमतों में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि 2009 में शुरुआत होने के बाद से अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 बिटकॉइन की कीमत 50 हजार डॉलर के पार हो गई है।

बिटकॉइन में तेजी का कारण

गौरतलब है कि पूरी दुनिया में अब बिटकॉइन की स्वीकार्यता काफी बढ़ी है, इसी वजह से लोग अब इस डिजिटल करेंसी में जमकर पैसे लगा रहे हैं। वहीं एप्पल और टेस्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी भी बिटकॉइन में इंवेस्ट कर रही हैं। पिछले हफ्ते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में 1.5 अरब डॉलर का बड़ा इंवेस्टमेंट किया है। वहीं कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों जैसे मास-म्यूचुअल, ऐसेट मैनेजर गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग, पेमेंट कंपनी स्क्वॉयर ने भी बिटकॉइन में बड़ा निवेश किया है इसी वजह से इसकी कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

क्या है बिटकॉइन

बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है और यह पहली विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ है कि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित पेमेंट के लिए इसे बनाया गया है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है, आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरुप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है।

6.24 अरब डॉलर घटा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, इसलिए आई गिरावट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच फरवरी को समाप्त सप्ताह में 6.24 अरब डॉलर घटकर 583.945 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.852 अरब डॉलर बढ़कर 590.185 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया था।

इसलिए आई गिरावट

भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पांच फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से मुद्रा भंडार में गिरावट आई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 4.88 अरब डॉलर घटकर 542.338 अरब डॉलर रह गई। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्रा सम्पत्ति भी शामिल होती हैं।

34.967 अरब डॉलर रहा स्वर्ण भंडार का मूल्य

आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.327 अरब डॉलर घटकर 34.967 अरब डॉलर रह गया। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार 60 लाख डॉलर घटकर 1.503 अरब डॉलर रह गया जबकि आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार भी 2.7 करोड़ डॉलर घटकर 5.138 अरब डॉलर रह गया।

क्या है विदेशी मुद्रा भंडार?

विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारियों का बुगतान करने में किया जाता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह आयात को समर्थन देने के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक मदद उपलब्ध कराता है। इसमें आईएमएफ में विदेशी मुद्रा असेट्स, स्वर्ण भंडार और अन्य रिजर्व शामिल होते हैं, जिनमें से विदेशी मुद्रा असेट्स सोने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं।

शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसे लुढ़ककर 72.92 प्रति डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार की सुस्ती और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसे कमजोर होकर 72.92 प्रति डॉलर स्तर पर आ गया। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 72.90 प्रति डॉलर पर खुला। कुछ देर में यह और गिरकर 72.92 प्रति डॉलर पर आ गया। यह पिछले दिवस के मुकाबले में 23 पैसे की गिरावट है। मंगलवार को रुपया 72.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर का सूचकांक 0.17 प्रतिशत बढ़कर 90.66 पर पहुंच गया। घरेलू बाजार के मोर्चे पर 30 शेयरों वाला बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 325.12 अंकों की गिरावट के साथ 51,779.05 अंक पर और एनएसई निफ्टी 89.40 अंकों की गिरावट के साथ 15,224.05 अंक पर कारोबार कर रहा था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार रहे। उन्होंने मंगलवार को 1,144.09 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इस बीच, कच्चा तेल का वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत बढ़कर 63.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

2020-21 के लिए जमा पर ब्याज दर चार मार्च को घोषित कर सकता है EPFO

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिटायरमेंट फंड बॉडी (EPFO) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चार मार्च को भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर की घोषणा कर सकता है। चार मार्च को श्रीनगर में ईपीएफओ की बैठक है। इस बैठक में 2020-21 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। ईपीएफओ के एक ट्रस्टी के मुताबिक, ट्रस्टियों के केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक श्रीनगर में चार मार्च को होनी है। जल्द ही इस बैठक का एजेंडा शेयर किया जाएगा। इस बात की अटकलें हैं कि ईपीएफओ इस वित्त वर्ष (2020-21) के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटा सकता है, जो 2019-20 के लिये 8.5 प्रतिशत थी।पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया था, जो 2018-19 में 8.65 प्रतिशत था। ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) 2019-20 के लिए दी की गई ब्याज दर 2012-13 के बाद से सबसे कम रही। ईपीएफओ ने 2016-17 के लिए अपने ग्राहकों को 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दर दी थी। 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी। इसने 2013-14 के साथ-साथ 2014-15 में 8.75 प्रतिशत ब्याज दर दी थी।

ऐसी संभावना है कि चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ब्याज दरों में कमी कर सकता है। दरअसल, कोरोना संकट के दौर में खाताधारकों ने पीएफ से बड़ी रकम की निकासी की है। दूसरी ओर यह तर्क भी है कि बड़ी संख्या में नौकरियां जाने से ईपीएफओ में जमा की जाने वाली रकम भी घटी है। मालूम हो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से नियमों में बदलाव के बाद इंइ से आंशिक या पूर्ण निकासी करना आसान और तेज हो गया है। ईपीएफओ ने कर्मचारी को जोब छोड़ देने के एक महीने के बाद ईपीएफ फंड से 75 फीसद तक की राशि की निकासी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन आंशिक निकासी कर सकते हैं।

जीएसटी के प्रावधानों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही केंद्र सरकार- फैम

रांची। एजेंसी

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फैम) की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि जीएसटी के प्रावधानों में केंद्र सरकार की ओर से निरंतर सरलीकरण की प्रक्रिया स्वागत योग्य कदम है। संगठन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की है। फैम के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम गाड़िया, महासचिव दीपेश निराला, मीडिया सेल के प्रदेश चेयरमैन संजय सर्राफ एवं कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन ने संयुक्त बयान जारी करअपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। कहा कि व्यवसायिक संगठनों की ओर से निरंतर दिए जा रहे सुझाव का केंद्र संज्ञान ले रहा है। इसके तहत अपेक्षित कार्रवाई की जा रही हैं।

फैम की तरफ से वित्त मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर दो फीसद एक्वालिसशन लेवी लगाने के निर्णय पर धन्यवाद दिया। फैम की तरफ से पांच फीसद की दर से एक्वालिसशन लेवी की मांग की गई थी। संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 42 महीने की अपनी यात्रा में जीएसटी के कानून और नियमों में कई बदलाव आए हैं। छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली सभी व्यावहारिक कठिनाइयों ने जीएसटी पर फिर से विचार करने का पर्याप्त कारण दिया है। भारत के 15 वें वित्त आयोग द्वारा भी अपनी हालिया टिप्पणी में इसकी तरफ इशारा किया गया है। व्यापारी वर्ग जीएसटी के कड़े एवं अव्यवहारिक अनुपालन से परेशान हैं। फैम के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जारी बयान स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी में हाल ही में किए गए परिवर्तन छोटे छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गए है। ऐसे में करों का सरलीकरण ही बेहतर कदम है। अब जब सरकार अपनी तरफ से सरलीकरण की बात कर रही है तो व्यापारी वर्ग को इस पर भरोसा रखना चाहिए। संगठन ने दावा किया कि फैम द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार अवश्य विचार कर लागू करेंगी। संगठन ने कहा कि हम कभी भी सड़क पर प्रदर्शन या भारत बंद आह्वान नहीं करते हैं। हमारा संगठन कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाता है, बल्कि हम बातचीत और चर्चा में विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने जीएसटी पर सरलीकरण पर अपना सुझाव देने के लिए वित्त मंत्री से बैठक की मांग की। फैम के झारखंड प्रदेश मीडिया सेल के चेयरमैन संजय सर्राफ ने बताया कि जिस प्रकार कंपनी एक्ट में छोटी कंपनी एवं बड़ी कंपनियों के अनुपालन में भिन्नता है , सरकार को भी जीएसटी में छोटे एवं माध्यम व्यापारियों पर एक बहुत सरल सी जीएसटी प्रणाली लगानी चाहिए जिससे छोटा व्यापारी बिना किसी पेशेवर के अपना जीएसटी टैक्स खुद जमा कर सके।

जीएसटी चोरी में समन या नोटिस पर सील होंगे बैंक खाते

जून-जुलाई तक लागू हो सकता है प्रस्तावित कानून

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार जीएसटी चोरी मामले में सख्ती और बढ़ाने जा रही है। बजट में जीएसटी से जुड़े प्रस्तावित कानून के मुताबिक, अगर किसी व्यापारी को जीएसटी चोरी मामले में समन या नोटिस मिलता है तो आयुक्त उसके बैंक खाते और प्रॉपर्टी को सील कर सकेंगे। फिलहाल किसी व्यापारी के बैंक खाते और प्रॉपर्टी को तभी सील किया जाता है, जब जीएसटी चोरी का मामला साबित हो जाता है। जीएसटी चोरी मामले में सीजीएसटी एक्ट की धारा 83 के तहत नोटिस या समन दिया जाता है। पहली फरवरी को पेश बजट में जीएसटी चोरी पर सख्ती के लिए कई नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है।

मार्च आखिर तक केंद्र की तरफ से इन बदलावों को अधिसूचित किया जा सकता है। राज्यों को भी अपने-अपने स्तर पर इन्हें अधिसूचित करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक जून-जुलाई तक प्रस्तावित कानून लागू हो जाएगा। प्रस्तावित कानून में ई-वे बिल में हेराफेरी और वस्तुओं के आवागमन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए बदलाव किए गए हैं। ई-वे बिल में हेराफेरी या नियमों का पालन नहीं करने पर होने वाले जुर्माने को चुनौती देने के लिए अपील में जाने के नियम में बदलाव का प्रस्ताव है। अपील में जाने के लिए जुर्माने की राशि का 25 फीसद पहले जमा करना होगा। सामान्यतः यह राशि 10 फीसद होती है।

जीएसटी कानून विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजिंदर अरोड़ा ने बताया कि सरकार के इन नियमों से निश्चित रूप से जीएसटी चोरी कम होगी। लोग किसी भी प्रकार की हेराफेरी करने के लिए हतोत्साहित होंगे। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या एक से दो फीसद तक ही होती है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि अन्य कारोबारियों को कानून में प्रस्तावित बदलावों से परेशानी न हो।

रुकेगा आइटीसी का गड़बड़झाला

प्रस्तावित कानून में निर्यात के नाम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के गड़बड़झाले को रोकने के भी उपाय किए जा रहे हैं। अभी निर्यातक अपना टैक्स लगाकर निर्यात कर देते हैं और वह टैक्स उन्हें कस्टम से रिफंड के रूप में मिल जाता है। प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि सरकार बताएगी कि किन-किन वस्तुओं के निर्यात में टैक्स लगाकर निर्यात किया जा सकता है और किन में नहीं। इसे लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से सूची जारी की जाएगी।

सख्ती से बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन

पिछले सालभर से जीएसटी चोरी के मामले में सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। रोजाना फर्जी बिलिंग और निर्यात के इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी जैसे मामले पकड़ में आ रहे हैं। इन मामलों में सख्ती से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिली है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को मोदी सरकार की प्राथमिकताएं बताईं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराया।आम बजट के बाद आरबीआई बोर्ड की यह पहली बैठक थी जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और इसे सतारमण ने भी संबोधित किया। परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री हर साल बजट प्रस्तुति के बाद आरबीआई तथा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड सदस्यों के साथ बैठक करते/करती हैं। बयान में कहा गया, बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक व घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की, जिसमें बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के तरीके भी शामिल हैं। मंगलवार को हुई बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक 'वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज भी बैठक में शामिल हुए। सीतारमण के अलावा, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे भी मौजूद थे।

आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 587वीं बैठक

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 587वीं बैठक को संबोधित किया और सदस्यों को बजट में महत्वपूर्ण पहल तथा सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उसने कहा, बजट पर वित्त मंत्री की सराहना करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचार के लिए कई सुझाव दिए। केंद्रीय निदेशक मंडल ने 2021-22 के बजट की प्रस्तुति के बाद अपनी पहली बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की।

1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात और इंटरनेट इस्तेमाल करना

दरें बढ़ाने की तैयारी में टेलिकॉम कंपनियां

मोबाइल से बात करना और उसपर इंटरनेट इस्तेमाल करना जल्द और महंगा होने वाला है। दूरसंचार कंपनियां इस साल 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में हैं। साथ ही उसके आगे भी दरों में वृद्धि जारी रह सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

कोरोना संकट और खासकर लॉकडाउन में जहां अन्य क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ीं। वहीं दूरसंचार कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) यानी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हुआ है। हालांकि, कंपनियों के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह बहुत नहीं है। ऐसे में कंपनियां मोबाइल दरों को बढ़ाकर उसकी भरपाई करने की तैयारी में हैं। इससे पहले, पिछले साल भी कुछ दूरसंचार कंपनियों ने दरों में इजाफा किया था।

उल्लेखनीय है कि कुल एजीआर का बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, अभी तक सिर्फ 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपये ही चुकाए हैं। एयरटेल पर करीब 25,976 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 50399 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज पर करीब 16,798 करोड़ रुपये का बकाया है। कंपनियों को 10 फीसदी राशि चालू वित्त वर्ष में और शेष बकाया राशि आगे के वर्षों में चुकानी है।

4जी से भी भर रही कंपनियों की झोली

इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक दरों में बढ़ोतरी और ग्राहकों का 2जी से 4जी में अपग्रेडेशन की वजह से भी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हो सकता है। मध्यम अवधि में यह करीब 220 रुपये हो सकता है, जिससे अगले दो साल में दूरसंचार उद्योग का का राजस्व 11 से 13 फीसदी तक बढ़ेगा। जबकि उसके बाद आपरेटिंग मार्जिन करीब 38 फीसदी बढ़ेगा।

एजीआर का बोझ ग्राहकों पर डालेंगी कंपनियां

रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों के नकद प्रवाह में सुधार हुआ है। इसके अलावा पूंजीगत खर्चों में कमी से नियमित कामकाज के लिए बाहरी कर्ज की आवश्यकता कम भी होगी। हालांकि, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) देनदारियों के साथ कर्ज और 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते टेलिकॉम कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कंपनियां इनका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।

रिलायंस के कदमों पर चली सरकारी कंपनी ओएनजीसी, जानिए क्या कर रही है!

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) गैस कारोबार के लिए एक अलग अनुषंगी कंपनी का गठन कर रही है। यह कंपनी उसकी (ओएनजीसी की) परियोजनाओं की गैस खरीद सकती है। ओएनजीसी के निदेशक मंडल ने नयी कंपनी के गठन के प्रस्ताव को 13 फरवरी को मंजूरी दी। इसके शत प्रतिशत शेयर ओएनजीसी के पास होंगे। यह जानकारी कंपनी की तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में दी गयी है। यह कंपनी गैस, एलएनजी, बायोगैस, मीथेन जैसे ईंधनों की खरीद, विपणन एवं व्यापार करेगी। इस घटनाक्रम के जानने वाले लोगों ने कहा कि ओएनजीसी की यह अनुषंगी केजी बेसिन की उनकी केजी-डी5 जैसी परियोजनाओं की गैस खरीदने के लिए भी बोली लगा सकती है। सरकार ने अक्टूबर 2020 के एक नीतिगत निर्णय के तहत गैस उत्पादकों से जुड़ी कंपनियों को उनसे खुली बोली के तहत गैस की खरीद की छूट दे दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सम्बद्ध कंपनी रिलायंस ओ2सी लि. ने इसी नीति के तहत पांच फरवरी को हुई नीलामी में गैस खरीदी थी।

रिकवरी के ट्रैक पर भारतीय अर्थव्यवस्था

ये 3 फैक्टर फूंक रहे जान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में उबरने की राह पर है। कृषि क्षेत्र के लगातार अच्छे प्रदर्शन, कोविड-19 के संक्रमण की कम होती रफ्तार और सरकारी व्यय में तेजी से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल रहा है। एसएंडपी ने कहा कि पुनरुद्धार जारी रखने के लिये भारत को कई चीजों को सही करने की जरूरत है। भारत को शीघ्रता से अपनी 1.4 अरब की आबादी को टीके लगाने की जरूरत है। एसएंडपी ने 'क्रॉस सेक्टर आउटलुकः इंडियाज एस्केप फ्रॉम कोविड' शीर्षक रिपोर्ट में कहा, "कोविड-19 के अधिक संक्रामक रूप लेने और टीके से उत्पन्न की जा रही प्रतिरोधकता को अक्षम बनाने से इस पुनरुद्धार को जोखिम पैदा हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो वित्तीय उपाय किये गये हैं, उन्हें समय से पहले वापस ले लिये जाने का भी जोखिम है।"

अभी भी महत्वपूर्ण जोखिम बरकरार

एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट भी अपेक्षित से अधिक खर्चों के माध्यम से पुनरुद्धार का समर्थन करेगा। भारत की वृद्धि की संभावनाएं उसके अधिक आक्रामक राजकोषीय रुख से जुड़े उच्च घाटे को संभाले रखने की क्षमता के लिये महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था स्थिरता से पुनरुद्धार की ओर बढ़ रही है और अभी भी महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना कर रही है। हम अनुमान लगाते हैं कि भारत उत्पादन के मोर्चे पर महामारी से पहले की गति की तुलना में एक स्थायी नुकसान का सामना करने जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 10 प्रतिशत के बराबर का दीर्घकालिक हो सकता है।

महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगी राहत!

क्या है सरकार की योजना, गडकरी ने किया खुलासा..

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत रेकॉर्ड पर पहुंच गई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर चढ़ कर 89.29 रुपये पर चला गया। डीजल भी 35 पैसे का छलांग लगा कर 79.70 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। भोपाल में तो XP पेट्रोल का दाम 100.18 रुपये प्रति लीटर पर चला गया। इस बीच सरकार ने वैकल्पिक ईंधन पर विचार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में वैकल्पिक ईंधन की जोरदार वकालत करते हुए मंगलवार को कहा कि अब इसका समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय देश में बिजली (Electricity) को ईंधन के रूप में बढ़ावा दे रहा है क्योंकि देश में जरूरत से ज्यादा (surplus) बिजली पैदा हो रही है। गडकरी ने कहा, 'मेरा सुझाव है कि देश में वैकल्पिक ईंधन का समय आ गया है। मैं पहले से ही फ्यूल के लिए इलेक्ट्रिसिटी को तरजीह देने के बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास सरप्लस बिजली है।' उन्होंने कहा कि 81 फीसदी लीथियम-आयन बैटरीज भारत में ही बन रही हैं। उनके मंत्रालय ने लीथियम-आयन के विकल्प के लिए भी पहल की है। सरकार की सभी लैबोरेटरीज इस दिशा में रिसर्च कर रही हैं। साथ ही मंत्रालय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को भी विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

अभी चीन का दबदबा

वैकल्पिक ईंधन के विकल्प खोजने के लिए हाल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने और डीआरडीओ, इसरो व सीएसआईआर के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद थे। लीथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अभी चीन जैसे देशों का दबदबा है। गडकरी ने इससे पहले हाल में कहा था कि भारत को एडवांस बैटरी तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जल्द नीति लाएगी। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य शक्तिशाली बैटरी के जरिये ई-वाहन क्षेत्र में नबंर 1 बनने का है। भारत अभी ई-वाहन के साथ ऑटोमोबाइल विनिर्माण में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है।

सोने में 717 रुपये और चांदी में 1,274 रुपये की गिरावट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 717 रुपए की हानि के साथ 46,102 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, इससे पहले मंगलवार को सोना 46,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1,274 रुपये की हानि के साथ 68,239 रुपये प्रति किलो ग्राम पर बंद हुई, जिसका पिछला बंद भाव 69,513 रुपये प्रति किलो था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, "सोने की वैश्विक कीमत में गिरावट के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 717 रुपये की गिरावट आई।" अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,786 डॉलर प्रति औंस था जबकि चांदी 27.10 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही।

रुपया पांच पैसे की गिरावट के साथ 72.74 रुपये प्रति डॉलर पर बंद

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के समक्ष डॉलर के मजबूत होने तथा घरेलू शेयर बाजार में हानि के बीच मुकाबले रुपया पांच पैसे की हानि के साथ प्रति डालर 72.74 (अस्थाई) के स्तर पर बंद हुआ। अन्तरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपये की विनिमय दर प्रति डालर 72.90 पर खुलने के बाद दिन में 72.72-72.92 के बीच रही। अंत में भारतीय मुद्रा पांच पैसे गिर कर प्रति डालर 72.74 पर टिकी। मंगलवार को डालर-रुपया बाजार 72.69 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.35 प्रतिशत बढ़कर 90.82 हो गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 400.34 अंक की हानि के साथ 51,703.83 अंक पर बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक, पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 1,144.09 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद की। इसबीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.60 प्रतिशत बढ़कर 63.73 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

महामारी के बाद देश में पहली बार इतनी बड़ी मैदानी मैराथन

इंदौर में शामिल होंगे 5500 से ज्यादा प्रतिभागी

एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स द्वारा 28 फरवरी 2021 को मैराथन का आयोजन एक्चुअल और वर्चुअल रेस में शामिल होंगे 10 हजार से ज्यादा प्रतिभागी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दौड़ लगाकर बीमारियों को भगाने का संदेश देने के लिए एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स (एआईएम) द्वारा 'येलो डायमंड इंदौर मैराथन' का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना और दूसरी बीमारियों से दूर रहने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और नियमित रूप से रनिंग करने की जागरुकता लाने के लिए रखी जा रही इस मैराथन की थीम 'दौड़ लगाओ, कोरोना भगाओ' रखी गई है। एआईएम द्वारा सात वर्षों से इस तरह की मैराथन रखी जा रही है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिभागी शामिल होते हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते अन्य बड़े शहरों में इस तरह की मैदानी मैराथन नहीं हो सकी, लेकिन इंदौर में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। प्रतिभागियों को टी शर्ट, बिब, टाइमिंग चिप और मास्क दिए जाएंगे।

एआईएम के प्रेसिडेंट डॉ. अरूण अग्रवाल ने बताया कि इंदौर सहित देश भर के कई शहरों जैसे बैंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर आदि में हर वर्ष बड़ी मैराथन होती है, जिनमें हजारों प्रतिभागी शामिल होते हैं लेकिन इस में महामारी के कारण कहीं पर भी बड़ी मैराथन नहीं हुई। इंदौर कई मामलों में अग्रणी हैं और जागरुकता के मामले में सबसे आगे रहने की परंपरा को निभाते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोरोना संबंधित सावधानियों का पूरा पालन होगा और रनर्स 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन में शामिल होंगे। इन तीनों में हर वर्ष 20 हजार से ज्यादा रनर्स शामिल होते हैं, लेकिन इस बार प्रतिभागियों की संख्या सीमित कर दी गई है। एक्चुअल मैराथन में करीब 5500 प्रतिभागी शामिल होंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, वे प्रतिभागी इनमें शामिल हो सकेंगे। उन्होने बताया कि 'येलो डायमंड इंदौर मैराथन' की एक्चुअल रेस नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी। सभी मैराथन पूरी होने के बाद प्रतिभागियों को स्टेडियम में टी शर्ट, मेडल, नाश्ता आदि प्रदान किए जाएंगे। 5 किमी. की मैराथन के प्रतिभागियों को टाइमिंग चिप नहीं दी जाएगी, जबकि बाकी दोनों मैराथन के प्रतिभागियों को चिप दी जाएगी, जहां तय स्थानों पर लगी मेट पर उन्हें समय दर्ज करवाना होगा। नियत स्थानों पर चिप के माध्यम से ऑटोमेटिक रनर्स की एंट्री दर्ज होगी और इसी के आधार पर मैराथन पूरी करना का समय तय किया जाएगा।

इस बार रेस नहीं, अवेयरनेस मैराथन

एकेडमी के सचिव विशाल मुदगल ने बताया कि रनिंग करना सबसे सस्ती और असरदार एक्सरसाइज है। इसके लिए महंगे उपकरणों, जिम आदि की जरुरत नहीं होती। सामान्य शूज के साथ भी रनिंग की जा सकती है। इस बार की मैराथन कोई रेस नहीं बल्कि अवेयरनेस मैराथन है, जो लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने और नियमित रूप से रनिंग करने की प्रेरणा जगाने के लिए रखी जा रही है।

घर, गार्डन, ट्रेड मिल कहीं भी रनिंग कर मैराथन में हो सकते हैं शामिल

श्री मुदगल ने बताया कि एक्चुअल मैराथन में प्रतिभागियों की संख्या सीमित होगी, लेकिन वर्चुअल रेस में संख्या की बाध्यता नहीं होगी। दोनों ही रेस के लिए उम्मीदवारों indoremarathon.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका शुल्क 300 रुपए रखा गया है। वर्चुअल मैराथन में प्रतिभागी अपने घर, गार्डन, कॉलोनी की सड़क, ट्रेड मिल कहीं पर भी रनिंग कर सकता है। तय समय पर भी दौड़ना जरूरी नहीं है। आयोजन के 24 घंटे के भीतर कभी भी अपनी सुविधानुसार रनिंग की जा सकती है। indoremarathon.in पर प्रतिभागी द्वारा स्क्रीन शॉट भेजने के तीन सप्ताह के भीतर एकेडमी द्वारा मेडल और टी शर्ट भेजे जाएंगे।

भारत की प्राथमिकत 7-8 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की होनी चाहिए: पूर्व आरबीआई गवर्नर

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने 2021-22 के बजट को 'काफी अच्छा' बताते हुए मंगलवार को कहा कि भारत की प्राथमिकता फिलहाल 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने पर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल निवेश के बजाए रोजगार सृजन पर भी प्राथमिकता देने की जरूरत है। जालान ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं जान पड़ता कि भारत 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा, "इस साल का बजट काफी अच्छा है...मुझे लगता है कि भारत की वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत रहनी चाहिए।" वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में 2021-22 में तीव्र गति से पुनरूद्धार के साथ आर्थिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि चालू वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। जालान ने कहा, "सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बार वृद्धि दर इस स्तर पर होगी, तब उसके बाद रोजगार का मुद्दा होगा। हमें केवल निवेश ही नहीं, रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए।" आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि 18 महीने में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 पूर्व के स्तर पर आ जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर पाएगा, उन्होंने कहा, "हम अभी 2021 में है। अभी चार साल का समय है। फिलहाल जो स्थिति है, उसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।" जालायान ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हम सालाना आधार पर यह कर सकते हैं। हम अगले साल के लिये लक्ष्य तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अगले पांच साल के लिये अंकों में कोई लक्ष्य तय कर सकते हैं।" जालान ने कहा कि आजादी के बाद भारत उन देशों में शामिल है, जिसने लोकतांत्रिक आधार पर बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा, "नीति निर्माताओं ने लोगों की आंकाक्षाओं के अनुरूप कदम उठाये। अगले 4-5 साल में भारत की मुख्य प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराने पर होना चाहिए।" जालान ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भारत ने बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की है। किसानों के आंदोलन से जुड़े सवाल के जवाब में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले में आपसी संवाद की कमी रही है। उन्होंने कहा, "लेकिन किसान जो चाहते हैं, उसपर बात तो होनी चाहिए। सरकार के लिये किसानों नीति संबंधी इच्छा का समाधान करना आसान है।" मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के किसान सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

रिलायंस जियो है भारत में स्ट्रीमिंग सर्विस की कामयाबी का राज - नेटफ्लिक्स

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मशहूर स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के संस्थापक और सह-सीईओ, रीड हेस्टिंग्स का मानना है कि भारत में डेटा की कीमतों में नाटकीय गिरावट के पीछे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का हाथ है और यही वजह है कि भारत में नेटफ्लिक्स जैसी अनेकों स्ट्रीमिंग सर्विस कामयाब हो पाई हैं। फार्चून्न इंडिया के साथ एक खास साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि महंगी डेटा कीमतों की वजह से भारत की गिनती दुनिया के सबसे कीमती डेटा मार्किटों में होती थी, रिलायंस जियो की लॉचिंग के बाद मात्र 4 वर्षों की अवधि में भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक माने जाने लगा। रिलायंस जियो की तारीफ करते हुए रीड हेस्टिंग्स कहते हैं कि जियो डेटा क्षेत्र में जो परिवर्तन लेकर आया है उसके कारण ही नेटफ्लिकस का बिजनेस चलता है अन्यथा हम सफल नही होते।

रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी की तरफ इशारा करते हुए रीड हेस्टिंग्स ने कहा 'हम भाग्यशाली थे कि जब हमने कंटेंट निर्माण में निवेश की शुरूआत की, उसी समय कुछ अन्य लोग इंटरनेट बदलने की दिशा में निवेश कर रहे थे'। बता दें कि नेटफ्लिक्स को भारत में अभी पांच साल पूरे हुए हैं।

'ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दुनिया के सबसे महंगे डेटा को दुनिया के सबसे सस्ते डेटा में बदल पाया हो, वो भी केवल चार साल में। साथ ही दुनिया की सबसे कम डेटा खपत की मार्किट को, दुनिया की सबसे उच्च खपत वाला मार्किट में से एक बना पाया हो। भारतीय इंटरनेट का परिवर्तन अभूतपूर्व है।' रीड हेस्टिंग्स का मानना है कि रिलायंस जियो दुनिया में सबसे उल्लेखनीय बदलाव लाया है।

ओएनजीसी इस साल केजी बेसिन से उत्पादन बढ़ाएगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने सोमवार को कहा कि वह केजी बेसिन ब्लॉक से इस साल मई तक प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाकर 25 से 30 लाख घन मीटर प्रतिदिन करेगी। इस क्षेत्र से कंपनी का उत्पादन 2023-24 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने देश के पूर्वी तट पर स्थित कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन में पिछले साल 5.07 अरब डॉलर की केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 परियोजना से गैस उत्पादन शुरू किया था। ओएनजीसी के निदेशक (वित्त) सुभाष कुमार ने निवेशकों से कांफ्रेंस कॉल में कहा, "संकुल-दो से गैस उत्पादन शुरू हो गया है। फिलहाल यहां से प्रतिदिन 3,20,000 घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन हो रहा है। मई के बाद से इसे बढ़ाकर 25 से 30 लाख टन घन मीटर प्रतिदिन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पादन औसतन 34 लाख घन मीटर प्रतिदिन और अगले साल 85 लाख घन मीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि 2023 या 2024 तक उत्पादन अधिकतम स्तर पर पर पहुंच जाएगा। ओएनजीसी केजी-डी6 में खोजे गये क्षेत्रों से उत्पादन शुरू करने के लिये 5.07 अरब डॉलर निवेश कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अगुवाई करेंगी भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव बनाये जाने की घोषणा की है।

सिन्हा ने सोमवार को यूएनसीडीएफ के कार्यकारी सचिव का पदभार संभाल लिया। यह पद यूएनसीडीएफ का सबसे वरिष्ठ पद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका जोर उन महिलाओं, युवाओं, लघु एवं मझोले उद्यमों को छोटे कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने पर होगा, जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। संस्थान का गठन 1966 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। यह कम विकसित देशों को छोटे कर्ज उपलब्ध कराता है। सिन्हा ने ज्यूडिथ कार्ल की जगह ली, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ 30 साल के करियर के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हो गये। संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक अचीम स्टीनर ने सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा, "दुनिया के सबसे अल्पविकसित देशों के लिये यूएनसीडीएफ का समर्थन महत्वपूर्ण है। मैं हमारे संगठनों के बीच आने वाले समय में मजबूत भागीदारी जारी रहने की उम्मीद करता हूं।"

किस देवता को कौन सा प्रसाद पसंद है, पढ़ें रोचक धार्मिक जानकारी

भारतीय पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था में देवी-देवता मानवीय स्वरूप में स्वीकार्य हैं। चूंकि सगुण की उपासना करते हैं, इसलिए सगुण की हम मानवीय रूप में ही आराधना करते हैं। उनका जन्म होता है, विवाह होता है। परिवार होता है, निवास, वाहन, बच्चे, पसंद के फूल, फल.... मौसम, महीना... सब कुछ ठीक वैसे ही जैसे इंसान के हुआ करते हैं। उसी के अनुरूप देवी-देवताओं के वाहन, मास, ऋतु, पसंदीदा फल, फूल, पूजा-पद्धति... मिष्ठान्न-नेवैद्य इन सबका का भी एक नियम है। जैसे केतकी के फूल पार्वती को चढ़ते हैं, किंतु शिव को नहीं। काला चना दुर्गा को नैवेद्य में भोग लगाया जाता है, लेकिन किसी अन्य देवता को नहीं। आइए जानें कि किस देवता को भोग में क्या प्रिय है

विष्णु का नेवैद्य

भगवान विष्णुजी को खीर या सूजी के हलवे का नेवैद्य बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कतरे हुए बादाम, बहुत थाड़ी-सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चारौली, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए एक इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी जरूर डालें। उसे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णुजी को भोग लगाने के बाद वितरित करें। मान्यता है कि प्रति रविवार और गुरुवार को विष्णु-लक्ष्मी मंदिर में जाकर विष्णुजी को उक्त उत्तम प्रकार का भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं।

शिव का भोग

शिव को भांग और पंचामृत का नेवैद्य पसंद है। भोले को दूध, दही, शहद, शकर, घी, जलधारा से स्नान कराकर भांग-धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। शिवजी को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी अर्पित की जाती है। श्रावण मास में शिवजी का उपवास रखकर उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध अर्पित करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है।

हनुमान को लगाएं भोग

हनुमानजी को हलुआ, पंच मेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोठ, डंठल वाला पान और केसर- भात बहुत पसंद हैं। इसके अलावा हनुमानजी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार कर हनुमानजी को चोला चढ़ाकर यह नैवेद्य लगाता है, तो उसके हर तरह के संकटों का अविलंब समाधान होता है।

मां लक्ष्मी को भोग

लक्ष्मीजी को धन की देवी माना गया है। कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। लक्ष्मीजी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मीजी को सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर-भात बहुत पसंद हैं। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मीजी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती।

दुर्गा माता को भोग

माता दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। दुर्गाजी को खीर, मालपुए, हलुआ, केले, नारियल और मिष्ठान्न बहुत पसंद हैं। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर माताजी को सभी तरह का हलुआ बहुत पसंद है, नवरात्रि में काला चना उनके नेवैद्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बुधवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा मां को विशेषकर नेवैद्य अर्पित किया जाता है। माताजी के प्रसन्न होने पर वह सभी तरह के संकट दूर होते हैं।

सरस्वती माता भोग

माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। ज्ञान कई तरह का होता है। स्मृतिदोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं। अतः माता सरस्वती के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है।

गणेश भोग

गणेशजी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में खासतौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर-घर में तरह-तरह के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलावा गणेशजी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद हैं। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उनको अर्पित किए जाते हैं।

भगवान श्री राम भोग

भगवान श्रीरामजी को केसर भात, खीर, धनिए का भोग आदि पसंद हैं। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी प्रिय है।

श्रीकृष्ण भोग

भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। इसके अलावा खीर, हलुआ और मावा-मिश्री के लड्डू पसंद हैं।

मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम के अनुसार पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वालों को मिलती है ये सजा

धर्म ग्रंथ रामायण में बालि के बारे में कहा जाता था कि वो किसी से भी युद्ध करते तो सामने वाले की आधी शक्ति उनमें आ जाती।

यही कारण था कि उन्हें हराना आसान नहीं था। बालि कभी किसी से युद्ध नहीं हारा। रावण जैसे योद्धा को उसने बुरी तरह से हराया। जो कोई भी बालि से लड़ने गया उसने मुंह की खाई। लेकिन बालि भगवान राम के तीर से मर गए। भगवान राम ने उन्हें छिपकर तीर मारा। तीर लगते ही वो जमीन में गिर गए। तीर मारने के बाद भगवान राम बालि के पास पहुंचे। बालि ने भगवान राम को कहा कि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर मुझे इस प्रकार क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में श्रीराम ने कहा- **अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी? इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई?**

इसका अर्थ होता है- किसी के भी छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री, ये सब समान होती है। जो कोई भी इन पर बुरी नजर डालता है, अगर ऐसे लोगों को मारा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। भगवान राम ने आगे कहा कि बालि, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखी और सुग्रीव को मारना चाहा। यही कारण था कि तुझे बाण मारा गया। श्री राम का ये जबाव सुनकर बालि संतुष्ट हो गया और श्रीराम से अपने पापों की क्षमा याचना की और अपने प्राण त्याग दिए। साथ ही बालि ने अपने बेटे अंगद को श्रीराम की सेवा में सौंप दिया।

साईंबाबा की आराधना ऐसे करें पूरी होगी सभी मनोकामनाएं

साईंबाबा को मानने वाले अनुयायियों और भक्तों की कमी नही हैं। वह एक संत और फकीर माने जाते हैं। साईंबाबा की आराधना बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन साईंबाबा का व्रत और आराधना करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग बृहस्पतिवार के दिन साईंबाबा की पूजा-अर्चना के साथ ही गरीब लोगों को भोजन भी वितरित कराते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि साईंबाबा अपने भक्तों की आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। साईंबाबा का व्रत 9, 11 या 21 बृहस्पतिवार तक ही रखने चाहिए। यदि आप भी साईंबाबा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी बृहस्पतिवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत रखने वाले को बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध मन से प्रातःकाल स्नानादि के बाद घर अथवा मंदिर में जाकर साईंबाबा के दर्शन कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन साईंबाबा का व्रत करने वाले को उनकी चालीसा और आरती भी अवश्य करनी चाहिए। साईंबाबा की शुद्ध मन से की गयी आराधना से व्रती की सभी इच्छायें अवश्य ही पूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त साईं बाबा के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति की जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन साईंबाबा का व्रत रखने वाले को इन मंत्रों का जाप करना चाहिए।

गरुड़ पुराण की बस 1 बात ध्यान में रख ली तो धन बरसेगा, सौभाग्य चमकेगा

गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ डराने या नरक की ही बाते हैं। किसी के यहां कोई मौत हो जाती है तभी गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है लेकिन यदि आप यूं ही एक बार गरुढ़ पुराण पढ़ लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और जीवन और मौत से जुड़ी बातों की आपको जानकारी मिलेगी। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बाते हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण की हजारों बातों में से एक बात यह भी है कि यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ-सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुण पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख-सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहननें चाहिए जिससे हम पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे।

बिल्कुल नए अंदाज़ में हुआ जावा 2.1 का लॉन्च

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जावा 2.1 के आगमन की घोषणा के साथ ही, जावा फोर्टी टू परिवार में तीन नए सदस्य शामिल हो गए। क्लासिक लेजेंड्स को इस बात की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि इसके मॉडल लाइन-अप में शामिल की गई नई बाइक्स कंपनी के सभी डीलरशिप में उपलब्ध होंगे। जावा 42 सही मायने में 'रेट्रो कूल' रिवॉल्यूशन को आगे ले जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इसके लॉन्च के साथ की गई थी और अब इसमें क्लासिक स्पोर्ट्स बाइक की विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। दिल्ली में इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1,83,942 रुपये है। इस नई मोटरसाइकिल के आगमन के बारे में बताते हुए, आशीष सिंह जोशी, CEO – क्लासिक लेजेंड्स ने कहा, 'पिछले साल हमने बाइक्स के BS6 वर्जन को लॉन्च किया। लेकिन हमारी कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई और हमने खुद से ही मुकाबला करते हुए अपने मोटरसाइकिलों के प्रदर्शन और अनुभव को ओर बेहतर बनाया है, जिसे हमने 2.1 का नाम दिया है। हमने एग्जॉस्ट नोट को और ज्यादा थ्रोटी तथा पहले की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया है, साथ ही हमने सीट का आकार बढ़ाया है तथा लुक को और जोरदार बनाने के लिए हमने क्रॉस पोर्ट इंजन में थोड़े सुधार किए हैं। हमारे ग्राहकों ने शुरू से ही जावा 42 का उपयोग अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक कैनवस के रूप में किया है। इस बात से प्रेरणा लेते हुए, हमने स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में 'क्लासिक स्पोर्ट्स' स्ट्राइप्स, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, ट्रिप मीटर और एक्सेसरीज़ के रूप में फ्लाई-स्क्रीन और हेडलैंप ग्रिल के साथ तीन नए कलर स्कीम को शामिल किया है। जावा और फोर्टी-टू बाइक्स की पूरी रेंज में टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी अपडेट उपलब्ध होंगे, साथ ही ग्राहकों के पास नए एक्सेसरीज़ चुनने का विकल्प भी होगा।'

टैफे ने लॉन्च की क्रांतिकारी डायनाट्रैक सीरीज़
कृषि और ढुलाई के लिए सबसे उपयुक्त ट्रैक्टर

चेन्नई। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी, और मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों की निर्माता, टैफे (ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड) ने अपनी नई डायनाट्रैक सीरीज़ लॉन्च की। डायनाट्रैक ट्रैक्टरों की एक उन्नत रेंज है जो बहुमुखी प्रदर्शन, परिष्कृत टेक्नोलॉजी, बेजोड़ उपयोगिता और अनेकों कार्य करने का सामर्थ्य - यह सब एक ही शक्तिशाली ट्रैक्टर में प्रदान करती है। टैफे की 60 से अधिक वर्षों की प्रमाणित इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, भारतीय कृषि की गहरी समझ और जानकारी ने कृषि और ढुलाई, दोनों के लिए ट्रैक्टरों की एक ऐसी प्रीमियम रेंज निर्मित करने में मदद की है, जो गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करती। नई डायनाट्रैक सीरीज़ को अच्छे माइलेज, मज़बूती और आराम सुनिश्चित करते हुए, अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डायनाट्रैक का डायनालिफ्टरु हाइड्रोलिक्स सिस्टम बेहतर लिफ्ट क्षमता, उत्पादकता और गति प्रदान करता है, जो सदा आपका साथ देगा, और इन खूबियों की वजह से यह ट्रैक्टर अपने सेगमेंट में शीर्ष पर पहुँच जाता है। वर्सटेकरू तकनीक वाला दुनिया का पहला ट्रैक्टर - डायनाट्रैक, एक्स्टेंडेबल व्हीलबेस प्रदान करता है, जो इसे पूरे साल कृषि, ढुलाई और कमर्शियल कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, जिससे यह पडलिंग और मेड़ों को आसानी से पार कर सकता है, तथा सभी इलाकों में परिचालन के लिए अपने वर्ग का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक्टर बन जाता है। इसका लंबा व्हीलबेस और स्टाइलिश हैवी-ड्यूटी अगला बम्पर ट्रैक्टर के समग्र लुक को बेहतर बनाते हैं और अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, तथा लोडर और डोज़र जैसे हेवी-ड्यूटी उपकरण को आसानी से संभालते हैं।

बजट में शामिल उपकर से राज्यों में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय बजट 2021-22 में लगाए गए कृषि उपकर के पैसे को अंततः कृषि मंडियों मंडियों और संबंधित खेती-बाड़ी के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि ये सुविधाएं राज्य सरकारों द्वारा ही संचालित की जाती है केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को इन आलोचनाओं को खारिज किया कि काई उपकर राज्यों को राजस्व से वंचित करता है। सरकारी सूत्रों ने उन खातों में ईपीएफ के ब्याज पर कर लगाने को भी सही ठहराया है, जहां कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक का ब्याज मिलता है। यह देखा गया था कि कई लोग 8.5 प्रतिशत से अधिक का सुनिश्चित ब्याज लाभ पाने के लिए ईपीएफ में करोड़ों रुपये जमा कराए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस कदम से ईपीएफ के कुल खाताधारकों में से केवल एक प्रतिशत प्रभावित होंगे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अनौपचारिक चर्चा में संवाददाताओं से कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अनिवार्य रूप से श्रमिकों और उन पर निर्भर रहने वालों के लिए है, ऐसे में यह उचित नहीं है कि कुछ लोग एक सुनिश्चित ब्याज लाभ पाने के लिए उसमें साल में एक करोड़ या दो करोड़ रुपये लगा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश किए गए बजट में कृषि उपकर सेलगभग 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है जो केंद्र सरकार के पास जाएगा।लेकिन सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस पैसे का उपयोग कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की मंडियों और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए किया जाएगा।

विनिर्मित वस्तुओं के महंगे होने से जनवरी में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.03 प्रतिशत

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के बाद भी थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में बढ़कर 2.03 प्रतिशत हो गयी। इसका मुख्य कारण विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी आना है। ताजे आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आयी। हालांकि विनिर्मित गैर-खाद्य वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली वर्ग का मूल्य सूचकांक बढने से मुद्रास्फीति बढ़ी । विशेषज्ञ अगले कुछ महीने में कीमत वृद्धि की दर के रफ्तार पकड़ने का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। थोक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति इससे पहले दिसंबर 2020 में 1.22 प्रतिशत और जनवरी 2020 में 3.52 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में शून्य से 2.8 प्रतिशत नीचे रही। यह एक महीने पहले यानी दिसंबर 2020 में शून्य से 1.11 प्रतिशत नीचे थी। इस दौरान सब्जियों की थोक मुद्रास्फीति शून्य से 20.82 प्रतिशत नीचे रहे पर

आलू की थोक मुद्रास्फीति इस दौरान 22.04 प्रतिशत रही। ईंधन एवं बिजली की मुद्रास्फीति शून्य से 4.78 प्रतिशत नीचे रही तबकि दिसंबर में इस वर्ग में मुद्रास्फीति शून्य से 8.72 प्रतिशत नीचे थी। गैर-खाद्य श्रेणी में मुद्रास्फीति इस दौरान 4.16 प्रतिशत रही। मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और मूल्य प्रशासन के तहत आने वाली वस्तुओं को छोड़ कर विनिमित चीजों के थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर) जनवरी 2021 में 27 महीने के उच्च स्तर 5.1 प्रतिशत पर रही। इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के असर को प्राथमिक खाद्य सामग्रियों के दामों में तेज गिरावट ने संतुलित कर दिया। इक्रा ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग तथा अधिक होती कीमतों के चलते अप्रैल-जून तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति सात से साढ़े सात प्रतिशत तक पहुंच सकती है। नायर ने कहा, ''अगले कुछ महीने में मुख्य थोक मुद्रास्फीति में तेज उछाल आ सकता है। हम अब वित्त वर्ष 2021-22 में औसत थोक मुद्रास्फीति पांच से साढ़े पांच प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रहे हैं, बशर्ते कि उपलब्ध टीके कोरोना वायरस के नये स्वरूपों के खिलाफ निष्प्रभावी साबित न हो जायें और इससे जिंसों की कीमतें, उपभोक्ताओं का भरोसा व कारोबारी धारणा कमजोर न हो जाये।'' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच फरवरी को मौद्रिक नीति घोषणा में ब्याज दरों को लगातार चौथी बैठक में अपरिवर्तित रखा। रिजर्व बैंक ने घोषणा करते हुए कहा था कि निकट-भविष्य में मुद्रास्फीति का परिदृश्य अनुकूल हुआ है।

मंत्रिमंडल ने भारत, मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) किये जाने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी । वहीं, सरकारी बयान के अनुसार, भारत और मॉरीशस सीईसीपीए पहला व्यापार समझौता है, जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है। यह एक सीमित समझौता है जिसके दायरे में वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय आयेंगे । इसमें कहा गया है कि सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ (80 श्रृंखला), कृषि उत्पाद (25 श्रृंखला), वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (27 श्रृंखला), आधार धातु और इनसे बने उत्पाद (32 श्रृंखला), बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (13 श्रृंखला), प्लास्टिक और रसायन (20 श्रृंखला), लकड़ी तथा लकड़ी से बने सामान (15 श्रृंखला) और अन्य शामिल हैं । मॉरीशस को अपने 615 उत्पादों के लिए प्राथमिकता की आधार पर भारतीय बाजार में पहुंच से लाभ मिलेगा। इनमें फ्रोजेन फिश, विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं । बयान में कहा गया है कि सेवा-व्यापार के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान और विकास अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विजुअल सेवाएँ और परिवहन सेवाएँ आदि के अंतर्गत से लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी। भारत ने इसके अलावा भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है । इसमें कहा गया है कि इस समझौते पर दोनों देशों के संबंधितों द्वारा पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उससे अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे।

बिजली कर्मचारियों के लिए मास्क भेंट किए रिलायंस फाउंडेशन ने

इंदौर। आईईपीटी नेटवर्क

देश के अग्रणी औद्योगिक समूह रिलायंस की ओर से कोविड से बचाव के लिए जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की टीम पोलोग्राउंड पहुंची एवं मास्क भेंट किए, कोविड से बचाव की जानकारी भी दी गई।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित मुख्यालय में रिलायंस फाउंडेशन मप्र की टीम बुधवार को पहुंची। इसमें टीम लीडर श्री शैलेंद्र जैन, मेम्बर श्री गौरव शर्मा, श्री विष्णु मिश्रा आदि शामिल थे। टीम ने प्रबंध निदेशक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आरके नेगी को कार्मिकों के लिए मास्क भेंट किए। इसी तरह पोलोग्राउंड में ही शहर वृत्त कार्यालय एवं ग्रामीण वृत्त कार्यालय में भी रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कर्मचारियों के लिए मास्क भेंट किए गए। टीम लीडर श्री शैलेंद्र जैन ने बताया कि बिजली वितरण के प्रत्येक जोन व वितरण केंद्र पहुंचकर भी मास्क वितरण एवं जागरुकता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने कोविड से बचाव के लिए रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित जनजागरुकता की इस पहल को प्रेरणादायी निरूपित किया है।

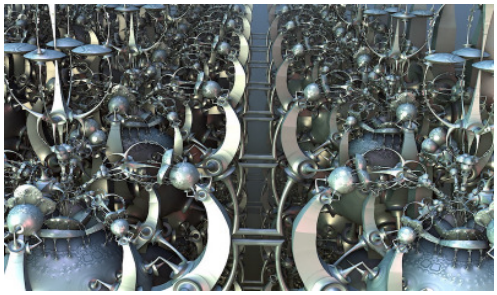

देश में बढ़ेगी टेलिकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग

12195 करोड़ की PLI स्कीम मंजूर

नई दिल्ली। एजेसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिये 12,195 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिये भारत को एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में आगे बढ़ा रही है। व्यापार करने में आसानी के लिये सरकार ने अनुकूल वातावरण बनाया है। मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिये PLI योजना को मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन होगा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट पीसी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये PLI योजना लायेगी।

बीमाधारकों को दस्तावेजों की सुरक्षा के लिये डिजिलॉकर सुविधा दें बीमा कंपनियां: इरडा

नयी दिल्ली। एजेंसी

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से अपने पॉलिसीधारकों को डिजिटल पॉलिसी जारी करने और इनका उपयोग करने का तरीका बताने को कहा है। नियामक ने कहा कि यह कदम न सिर्फ लागत कम करेगा बल्कि दावे को निपटाने की प्रक्रिया भी तेज करेगा। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (इरडा) ने जीआईसी आरई, लॉयड्स (इंडिया) और एफआरबी (विदेशी री-इंश्योरेंस ब्रांच) को छोड़कर सभी बीमा कंपनियों को जारी एक परिपत्र में कहा कि डिजिलॉकर लागत में कटौती करेगा। यह पॉलिसी कॉपी की डिलीवरी न होने से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने, बीमा सेवाओं के तेज प्रसंस्करण, शीघ्रता से दावों के निपटान, विवादों में कमी, धोखाधड़ी पर लगाम, उपभोक्ताओं तक बेहतर पहुंच समेत कई सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इरडा ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है।

आरबीआई ने निवासी व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को पैसा भेजने को मंजूरी दी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को पैसा भेजने को मंजूरी दे दी। आरबीआई के इस निर्णय का मकसद आईएफएससी में वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना और निवासी व्यक्तियों को उनके निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाना है। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने एलआरएस पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की और निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2005 के तहत स्थापित आईएफएससी में धन भेजने को मंजूरी देने का निर्णय किया। आरबीआई ने कहा कि पैसा केवल आईएफएसी में प्रतिभूतियों में निवेश के लिये भेजा जा सकेगा। इसके अलावा निवासी व्यक्ति एलआरएस के तहत स्वीकृत निवेश के लिये आईएफएसी में बिना ब्याज वाला विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकते हैं। आरबीआई ने कहा, "इस खाते में कोई भी कोष अगर प्राप्ति से 15 दिन तक निष्क्रिय पड़ा रहता है, उसे तुरंत भारत में निवेशक के घरेलू आईएनआर खाते में भेज दिया जाएगा।"

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।